MESSAGES FROM THE LOK SABHA-*Contd.*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Okay. Now Message from Lok Sabha. Secretary General.

The Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015

SECRETARY-GENERAL: Sir, I have to report to the House the following message received from the Lok Sabha, signed by the Secretary-General of the Lok Sabha:-

"In accordance with the provisions of rule 96 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, I am directed to enclose the Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2015, as passed by Lok Sabha at its sitting held on the 3rd March, 2015."

Sir, I lay a copy of the Bill on the Table.

SHORT DURATION DISCUSSION

Losses suffered by farmers due to recent rains in various parts of country - *Contd..*

श्री प्रमोद तिवारी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, एक बहुत ही संवेदनशील विषय पर प्रो0 राम गोपाल जी ने जो खुलकर अपने विचार रखे हैं, मैं अपने आपको उनसे सम्बद्ध करता हूं। खन्ना साहब अपने विचार कुछ डरे हुए ढंग से रख रहे थे, मैं उनसे भी अपने आपको सम्बद्ध करता हूं।

महोदय, मेरे पास ये रिपोर्ट्स हैं, जिनमें कोई कह रहा है कि पिछले 25 सालों में मार्च के महीने में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, एक रिपोर्ट कह रही है कि 100 सालों में कभी मार्च के महीने में इतनी ज्यादा बारिश नहीं हुई, कोई कह रहा है कि 25 परसेंट damage है और कोई कह रहा है कि 40 परसेंट damage है। महोदय, यह स्थिति एक, दो या तीन जिलों में नहीं है। यह स्थिति भारत के बहुसंख्यक हिस्सों में है, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, देश के बहुत से राज्य इससे बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। सच पूछिए, तो पानी नहीं बरसा है बल्कि तबाही बरसी है, बरबादी बरसी है। पानी के साथ कहीं-कहीं ओले भी पड़े हैं। जब पानी बरस रहा था, ओले पड़ रहे थे, उसके साथ तेज हवा भी चल रही थी, जिससे फसलें गिरी हैं और इसका दायरा बहुत बढ़ा है। हम इस तरह इसका आकलन न करें कि किसान को जो मिलने वाला था, उसका कितना नुकसान हुआ है। सच्चाई तो यह है कि किसान के घर में जो रखा था, वह भी चला गया, क्योंकि देखिए, यह बारिश किस वक्त हुई? जब जुताई हो गई थी। इसमें किसान की लेबर लगी होगी, बुआई हुई थी तो उसने उसके लिए बीज

खरीदा होगा, बीच में जो दो-तीन सिंचाई हुईं, तो उसके लिए भी किसान ने पैसा घर से दिया होगा, फर्टिलाइजर भी डाला होगा और मौजूदा सरकार में फर्टिलाइजर ब्लैक में ज्यादा मिल रहा है, तो वह फर्टिलाइजर भी महंगा पड़ा होगा। किसान का अनाज तो गया ही, सबसे बड़ी दिक्कत जो आगे चलकर आएगी, वह रबी की फसल का जो भूसा बनता है, जो जानवरों का चारा होता है, वह भी गया। शायद आदमी के खाने की दिक्कत न हो, क्योंकि हो सकता है कि बहुत से गोदामों में रखा हो, लेकिन जानवरों का यह जो चारा गया है, यह भी किसान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या होगी। आलू खत्म, आम खत्म, गेहूं, अंगूर, कपास, जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा फॉरेन करेन्सी मिलती थी, थोड़ा-बहुत एक्सपोर्ट कर लेते थे, वह भी चला गया।

महोदय, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि इसकी जो टाइमिंग थी, वह बहुत खराब थी। यह टाइमिंग वह थी, जब फसल पक चुकी थी। फसल पकने और कटाई के बीच में, कटाई कहीं-कहीं शुरू भी हो गई थी, क्योंकि सामान्यतया होली उत्तर प्रदेश में एक त्योहार की तरह मनाई जाती है और जो फसल की पहली कटाई होती है, वह होली को अर्पित की जाती है। सभी किसान अपनी बाली लेकर इसलिए तैयार थे कि जब होली जलेगी, तो वे उसके सामने लाकर काम शुरू करेंगे। ...(**व्यवधान**)... जी हां , बंगाल में कई जगह होता है। तो इसे सिर्फ अनाज के रूप में न लिया जाए, फसल के रूप में न लिया जाए, यह जो फसल आती, इससे जो पैसा आता, उससे बच्चे की पढ़ाई की फीस जमा होती, जो जुलाई में उसको देनी होती है। देहातों में यह परंपरा है कि शादियां ज्यादातर गर्मियों में होती थीं और गर्मियों में इसलिए होती थीं कि जब यह रबी की फसल कट जाती थी उससे लड़कियों की शादी में मदद होती थी। इसलिए लोग हमेशा बच्चों की शादियां अप्रैल, मई में करते थे। ...(**व्यवधान**)... तो मैं यह कहना चाहता हूँ कि ना-जाने कितने बच्चों की पढ़ाई रुक जाएगी, ना-जाने कितने किसानों को लड़कियों की शादी के लिए कुछ दूसरा काम करना पड़ेगा। अब इस साल तो फसल होगी नहीं, उसका कुछ मिलेगा नहीं, घर में जो रखा था वह भी चला गया। पता नहीं कितनी हमारी बेटियों के हाथ पीले होने से रह जाएंगे? फिर जो कर्जा ले रखा है, कर्जा अदा करने का सीजन भी यही होता है। इसी समय फसल काट कर वह कर्ज अदा किया जाता है। शुरुआत हो गई है, अगर देश में सबसे ज्यादा कहीं आत्महत्याएं हुई हैं, तो वे गुजरात और महाराष्ट्र में हुई हैं। मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि वहां किसकी सरकार है। मैं कृषि मंत्री जी से एक आग्रह करना चाहता हूँ, सीधे-सादे आदमी हैं, पता नहीं उनकी हिम्मत कहने की पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वे शरीफ आदमी हैं। जया जी, आप कृषि मंत्री जी से एक बात कहकर हमारी सिफारिश कर दीजिए।

श्रीमती जया बच्चन (उत्तर प्रदेश): मैं?

श्री प्रमोद तिवारी: सर, हमेशा एक बात होती है, कुछ बढ़-चढ़ कर नहीं बोलना चाहिए। डीजल और पैट्रोल के जब दाम कम हुए, तो त्यागी जी, मैंने भाषण सुना था कि मैं नसीब वाला हूँ, मेरे नसीब से दुनिया के बाजार में पैट्रोल, डीजल का दाम कम हो गया, इसलिए हम को ही चुनो। जो बातें उस दिन अहंकार में कही गईं, उसकी कीमत आपने दिल्ली में चुका दी और बिहार में भी तय है कि आप कीमत चुकाएंगे। वह तो हुआ, लेकिन गलती आपकी, जो आपने प्रकृति को चुनौती दे दी। मैं तो यह कहता हूँ

[श्री प्रमोद तिवारी]

कि यह जो ओले पड़े हैं, जो आंधी आई है, जो तूफान आया है, जो बरबादी आई है, वह आपके उस बयान के चक्कर में आई है। जरा कह दीजिए कि अहंकार में उतना ही बोला जाए, जितना जायज़ हो। प्रकृति को चुनौती देना ठीक नहीं है। क्या मैं यह कहूं कि पेट्रोल और डीजल का दाम कम हुआ, तो आपके नसीब से हुआ और अब यह जो ओले और पत्थर पड़े हैं, यह भी तो आपका ही नसीब है, क्योंकि इस समय राजा तो आप हैं।

महोदय, मैं एक चीज और बता दूं। देहात की परम्परा है कि घर जो टूटा होता है, उसका छप्पर खराब हो गया है, उसकी मरम्मत भी रबी की फसल कटने के बाद होती है, क्योंकि उस समय लेबर भी खाली होता है। अब ओले और बारिश ने तो फसल बरबाद कर दी। अब कैसे होगी इस घर की और छप्पर की मरम्मत?

महोदय, मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूं। अभी श्री अविनाश राय खन्ना इंश्योरेंस की बात कह कर चले गए। मैं 35-36 साल से किसी न किसी हाउस का इलैक्टेड मैंबर हूं। मेरा तो अनुभव यह है कि मैं इंश्योरेंस की बात सिर्फ भाषणों में सुनता रहा हूं। किसी किसान के घर इंश्योरेंस का पैसा जाते नहीं देखा। कभी जिला यूनिट बना देते हैं, कभी ब्लॉक यूनिट बना देते हैं, कभी पंचायत यूनिट बना देते हैं और जिस किसान का ओले में नुकसान होता है, उसके नुकसान की भरपाई मैंने इंश्योरेंस के पैसे से होते हुए कभी नहीं देखी। इसलिए मैं कृषि मंत्री जी से पहला अनुरोध यही करूंगा कि आप जब उचित समझें, सदन को यह बता दें कि इस ओले से, इस तबाही से, इस बाढ़ से किसान का कितना नुकसान हुआ और इससे किसान की आने वाली फसल भी गई और किसान के घर रखी पूंजी, सिंचाई, गुड़ाई, जुताई, फर्टीलाइजर में गई। उसके लिए आप कितना इंश्योरेंस दिला पाए और कितने लोगों को दिया गया, यह सदन को आप जरूर बताएं। कृषि मंत्री जी, चूंकि वित्त मंत्रालय आपके अंतर्गत नहीं आता, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि कृपया वित्त मंत्री जी से बात कर के इसे सुनिश्चित कर लें कि जिस जिले में या जहां भी क्षति हुई हो, हर किसान के लिए इंश्योरेंस की स्कीम के तहत पैसा उस तक पहुंचे, यह केन्द्र सरकार का काम है और इसे केन्द्र सरकार कराए।

महोदय, मैं दूसरा निवेदन यह करना चाहता हूं कि बैंकों के लोन की वसूली तत्काल बन्द करने के आदेश जारी होने चाहिए क्योंकि जो बैंकों के लोन हैं, ये बड़ी मुसीबत ढहाते हैं। अब बैंकों के लोन को रिकवर करने के लिए इलाके के गुंडे हायर किए जाते हैं। उन्हें आउट-सोर्सिंग के नाम पर वसूली के लिए रखा जाता है और वे किसानों को बेइज्जत करते हैं। जब परिवार के सामने, अपने बेटे-बेटियों के सामने किसान बेइज्जत और अपमानित होता है, तो आत्महत्या करता है। किसान तभी आत्महत्या करते हैं जब ये बैंक अपने कर्जे की वसूली में इस तरह की हरकतें करते हैं और किसान को अपने परिवार, अपने समाज के सामने अपमानित करते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि बैंकों की वसूली तत्काल रोक दी जाए। ये आदेश भारत सरकार आज ही जारी करे। यह आदेश प्रदेश सरकारें जारी नहीं कर सकतीं। वे अपने बकाये को वसूलने से रोक सकती हैं। इसलिए केन्द्र सरकार करे।

कृषि मंत्री (श्री राधा मोहन सिंह) : माननीय सदस्य, क्या आप मेरा भाषण होने तक रुकने वाले हैं?

श्री प्रमोद तिवारी: क्या आप आज ही बोलेंगे?

श्री राधा मोहन सिंह: जी हां। यदि आप न रुकने वाले हों, तो हम आपकी बात का जवाब दे दें। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रमोद तिवारी: मैं वैसे ही सुन लूंगा, जैसे प्रधान मंत्री जी, अपने में कमरे सुनते हैं। वैसे ही मैं यदि यहां नहीं रहा, तो अपने घर में जाकर टेलीविजन पर देख और सुन लूंगा।

श्री राधा मोहन सिंह: सर, हम तो आपसे बात कर रहे हैं। प्रधान मंत्री की बात नहीं कर रहे हैं।

श्रीमती जया बच्चन: सर, एक परम्परा है कि जो भी व्यक्ति किसी भी विषय पर बोलता हो, उन्हें पूरी डिबेट तक बैठना चाहिए। This is the courtesy that you give to the Bill that you are talking on.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Minister is here; Cabinet Minister is here; Minister of State is here. ...*(Interruptions)*...

श्री प्रमोद तिवारी :सर, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। वह परम्परा मैं निभाऊंगा और श्रीमती जया जी से भी अनुरोध करूंगा कि वे बैठी रहें।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं और उसे कह कर मैं अपनी बात समाप्त कर दूंगा। उत्तर प्रदेश से यह सरकार क्यों नाराज़ है, यह मैं नहीं जानता। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से लखनऊ में मैट्रो चलाने की स्कीम आई है, लेकिन आप उसे स्वीकृति प्रदान नहीं कर रहे हैं। जितनी स्कीमें उत्तर प्रदेश सरकार यहां भेजती है, केन्द्र सरकार उन्हें अनापत्ति प्रमाणपत्र देने में दिक्कत करती है। मैंने लखनऊ की मैट्रो का अभी खासतौर से जिक्र किया। उत्तर प्रदेश सरकार की तमाम स्कीमें यहां पड़ी हुई हैं। मेरा निवेदन है कि उन्हें तो स्वीकृति प्रदान कर ही दीजिए। इसके साथ ही साथ हाल में हुई ओला वृष्टि में तो कम से कम मानवीय आधार रखिए। इसमें यह मत देखिए कि कहां भाजपा की सरकार है या कहां गैर-भाजपा सरकार है। चूंकि मैं उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में मैं आपके सामने दो मांगें रख रहा हूं। पहली यह कि इस बारिश, ओलावृष्टि, तेज हवा, तूफान से सर्वाधिक प्रभावित यदि कोई प्रदेश है, तो वह उत्तर प्रदेश है। इसलिए मैं चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश को स्पेशल पैकेज के नाम से कम से कम 10 हजार करोड़ रुपए भारत सरकार तत्काल जारी करे, जिससे कि वहां भरपाई हो सके। मैं इन शब्दों के साथ, हमारे बहुत से साथी इसमें अपनी बात को जोड़ेंगे, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसको मानवीय आधार पर लिया जाए, दलीय आधार पर न लिया जाए। बैंक के कर्ज़े तत्काल खत्म हों। जिस किसान की क्षति हुई हो, उसको इंश्योरेंस मिल जाए, और एक बात, फिर मैं जोड़ देना चाहता हूं कि दस हजार करोड़

[श्री प्रमोद तिवारी]

रुपए का स्पेशल पैकेज उत्तर प्रदेश सरकार को इस तबाही और बरबादी से निपटने के लिए दिया जाए और अंतिम बात जो मैंने कही कि ज़रा बड़बोलापन कम किया जाए।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Shri Balwinder Singh Bhunder wants to go early. He is not well. If the House permits, I will call him before Shri K.C. Tyagi. Okay, Shri Balwinder Singh Bhunder.

श्री बलविंदर सिंह भुंडर (पंजाब) : चेयरमैन साहब, मैंने कल ही कहीं किसी पेपर में पढ़ा था कि 1925 में मिस्टर डॉलर ने, जो एक अंग्रेज़ था, उसने लिखा था कि हिंदुस्तान का किसान कर्ज़े में पैदा होता है, कर्ज़े में ही जीता है और कर्ज़ा लेकर ही मरता है। यह 1925 में भी सच था और आज भी सच है। जैसे कुदरत की जो बारिश है, इसको हम नियामत समझते हैं, लेकिन वह अब तबाही बन गई। किसान परमात्मा के भरोसे है, लेकिन वही बारिश आज किसान की तबाही का कारण बन गई है। कभी ओले पड़ जाते हैं, कभी सूखा पड़ जाता है, तो किसी न किसी तरह किसान पर मार पड़ती रहती है। इसलिए जो इतनी ज्यादा बारिश हुई, अगर यह थोड़ी होती तो अच्छी होती, लेकिन यह ज्यादा हो गई, तो इसके साथ बरबादी हो गई। इस बरबादी के लिए मैं एक बात यह कहना चाहता हूं, टाइम कम है, दूसरे सदस्य भी बोलेंगे, कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स को जो मुआवज़ा देती है, वह सिर्फ 1500 रुपए प्रति एकड़ देती है। आज 1500 रुपए का तो बीज भी नहीं आता। उसकी पिछली फसल भी गई, अगली भी गई, उस पर ब्याज भी आ गया, तो इसके लिए पहली बात तो मैं ऑनरेबल मिनिस्टर साहब... प्लीज़... मंत्री जी, हम जो कहना चाहते हैं, आप थोड़ा सा सुन लें। सबसे जरूरी बात है कि किसान को किसी भी कुदरती करोपी के कारण अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट फंड जो देता है, तो 100 परसेंट उसका लॉस होता है, जबकि सिर्फ 1500 रुपए प्रति एकड़ वह उसको देता है। अगर लॉस कम है, तो उससे भी कम हो जाता है और जो इरिगेटेड लैंड है और जो बारानी है, उसका 700 रुपए प्रति एकड़ है, तो आज के हिसाब से इस 1500 रुपए की कोई वैल्यू है? इसलिए इसको कम से कम 15,000 रुपए प्रति एकड़ करना चाहिए।

नंबर दो, जैसी तबाही कल हुई, उसमें छः महीने लग जाते हैं, तो पहले तो किसान का जो बैंक का लोन है, उस पर आज ही ब्याज बंद करना चाहिए और उसे लाँग टर्म का करना चाहिए। फिर उसका जो पिछला लॉस है, उसको कवर करने के लिए... है तो बड़ी पुरानी बात, बीस-तीस सालों से हम सुनते आ रहे हैं, जैसे ऑनरेबल मेम्बर साहब भी कह रहे थे कि जो क्रॉप इंश्योरेंस है, उसको कभी किसी स्कीम के साथ जोड़ देते हैं, कभी किसी के साथ जोड़ देते हैं। मैं तो यह भी कहना चाहता हूं कि जो कॉमर्शियल इस्टीट्यूशन है, उससे किसान क्या पालता है? उससे किसान किसी को कुछ नहीं दे सकता, इसलिए इसके बजाय गवर्नमेंट अपनी एजेंसी से, एल.आई.सी. से किसान की बीमा योजना को चालू करे। वह यह न देखे कि गांव है या ब्लॉक है या तहसील है, किसान का एक खेत भी मर जाता है। कई बार एक-एक किलोमीटर, कई दफा एक-एक फर्लांग में पट्टी लंबी तुरी जाती है, लेकिन गांव का वह one-tenth भी नहीं बनता, इसलिए वे सब रह जाते हैं। इसलिए अगर एक पट्टी में उसका बीस

एकड़, तीस एकड़, सौ एकड़ का नुकसान है तो उसको भी सौ परसेंट में लेकर नई पॉलिसी में शामिल करना चाहिए और जो बीमा योजना है, इसको किसी न किसी तरीके से ऐसा बनाना चाहिए कि किसान को उसका मुआवज़ा मिल सके। इस समय भी देश में किसान सबसे ज्यादा हैं, लेकिन जहां इंडस्ट्री का झगड़ा होता है, इंडस्ट्री का कितना ही लॉस हो जाए, उसका जो लोन है, वह भी एन.पी.ए. में पारित है और कई दफा माफ कर देते हैं, लाखों-करोड़ों की फिगर्स हैं, जो आप सब पढ़ते हैं। अगर फैक्टरी में आग लग जाए, कॉटन में लग जाए, कहीं और लग जाए तो उसको इंश्योरेंस मिल जाता है, लेकिन जो गरीब किसान है, जो देश का अन्नदाता है, जिसके ऊपर सब आधारित हैं, फैक्टरी भी उस पर चलती है, मज़दूर भी उस पर पलता है, यह सरकार भी उस पर चलती है, तो अगर आज देश में सूखा, अकाल पड़ जाए, तो देश का सारा सिस्टम डाउन हो जाता है, सारी फैक्टरियां बंद हो जाती हैं, मज़दूर बेकार हो जाते हैं। इसलिए इसका असर अकेले किसान पर नहीं पड़ता। फर्स्ट, जो किसान है, उस पर, उसके बाद उसके साथ जो मजदूर है, उस पर, तीसरा, जो मार्किट में आढ़ती है, उस पर और चौथा,जो दुकानदार उसका सामान बेचता है, उस पर भी उसका असर होता है। अगर किसान के पास कुछ है नहीं तो मार्किट भी बंद हो जाएगी। इसलिए इसका असर बहुत साइड्स पर पड़ता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी, जो प्वाइंट्स अभी जरूरी हैं, उन पर तुरंत ध्यान दे। उन्हें तुरंत लाँग टर्म लोन दे और उस पर ब्याज खत्म करे, जिससे इस पर आगे कोई ब्याज न लगे, वरना इसका कोई फायदा नहीं होगा। दूसरा, उनका मुआवजा बढ़ाना चाहिए और उसके टाइम पीरियड की ओर भी ध्यान देना चाहिए कि एक महीने या दो महीने के अंदर उनको मुआवजा दे देना चाहिए क्योंकि हम देखते हैं कि इसमें साल-साल का समय भी लग जाता है। तीसरा, मैं भी इस बात को समझता हूं कि यह काम अभी तो नहीं हो सकता है, बीस साल से यह झगड़ा चल रहा है, लेकिन जो इंश्योरेंस है, उसके लिए भी हमें यत्न करना चाहिए। चौथा, नेक्स्ट क्रॉप के लिए उसको रिलीफ देना चाहिए कि बैंकों से उसे फिर लोन मिल जाए। पांचवां प्वाइंट मैं यह कहना चाहता हूं कि ठीक है, कल बजट भी आया है और उसमें 8.5 लाख करोड़ का लोन उन्हें दे दिया। लोन तो दे दिया, गरीब लोन तो ले लेगा, लेकिन ब्याज कहां से देगा? जब फसल ही मर गयी तो वह ब्याज कहां से देगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो लोन देते हैं, आगे आने वाले वक्त में भी देते हैं, उसको चार परसेंट के सिम्पल रेट ऑफ इंटरस्ट पर देना चाहिए क्योंकि कम्पाउंड इंटरस्ट लगाने से वह बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए सिम्पल रेट ऑफ इंटरस्ट पर उसे लोन देना चाहिए और लाँग टर्म के लिए देना चाहिए, यह मैं कहना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार, किसानों पर इस समय जो आफत आयी है, उसमें उनके काम आएगी। धन्यवाद।

श्री के.सी. त्यागी (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कई बार कृषि को लेकर चर्चा हुई है। अभी एक महीना पहले हम महाराष्ट्र की कई जगहों पर सूखा पड़ने और अल्प वर्षा होने को लेकर चिंतित थे और आज अधिक वर्षा होने, ओलावृष्टि होने, हवाओं के तेज चलने के कारण जो लाखों-लाख किसानों का नुकसान हुआ है, उस पर प्रो0 राम गोपाल यादव जी के द्वारा जो चर्चा प्रारम्भ की गयी, उस पर बहस करने के लिए हम यहां हाजिर हैं। मुझे प्रसन्नता है कि जो दोनों मंत्री हैं, वे ग्रामीण पृष्ठभूमि के हैं। आज मैंने मंत्रियों की सूची तैयार की थी, उसके अनुसार 63 मंत्री हैं, जिनमें से

[श्री के.सी. त्यागी]

9 लोगों ने अपने गांव के पते लिखे हैं, उनमें ये दोनों भी शामिल हैं। मैं इस बात के लिए भी प्रसन्न हूं कि इन्होंने अपना गांव और डाकखाना भी उसमें दर्ज कराया है, एक पूर्वी चम्पारन का है और एक कुतबा, कुतबी का है। जो गांव के लोगों की तकलीफ है - असल में अभागापन हमारा यह है कि सरकार भी हमसे खफा है और कुदरत भी हमसे खफा है। सरकार की तरफ से भी इस सेक्टर के लिए जिस तरह का काम होना चाहिए, वह नहीं हो रहा है। हम जब ग्रोथ की बात करते हैं तो जो ग्रोथ है, वह exclusive होगी या देश के कुछ खास हिस्सों के लिए होगी? उनका ज्यादा ध्यान इंडस्ट्री पर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, corporate sector पर है, urban development पर है, वरना ऐसा क्या कारण है कि 67 साल की आज़ादी के बाद सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश की सिर्फ 40 या 42 परसेंट जमीन irrigated हो पायी? ये समस्याएं पिछले 67 साल से आ रही हैं, कोई दो दिन की नहीं हैं - कभी अल्पवर्षा होगी, कभी सूखा पड़ेगा, कभी अतिवृष्टि होगी, कभी ओलावृष्टि होगी और ये जो दिन चल रहे हैं, उनमें पाला पड़ेगा। बचपन में जब हम गांव में रहते थे, इधर तो शायद कुछ कम चलन हुआ है, जो कीट प्रकोप था, जैसे टिड्डी का आ जाना – हमने देखा है कि टिड्डी आयी और पूरे के पूरे इलाके को समाप्त करके चली गयी, लेकिन उस जमाने में टिड्डी को प्राकृतिक प्रकोप नहीं माना जाता था। मैंने माननीय मंत्री महोदय से निवेदन किया था, शायद कई सदस्यों को ताज्जुब भी होगा कि आसमान से जो बिजली गिरती है, उसमें हजारों मौतें हुई हैं और 90-99 परसेंट मौतें किसानों की हुई हैं, लेकिन उसको प्राकृतिक प्रकोप का हिस्सा अभी तक नहीं माना गया है। जो प्राकृतिक प्रकोप के जरिए होने वाली जान-माल की हानि है, उसके तहत जो मुआवजा मिलना चाहिए, वह भी उनको अब से कुछ दिन पहले तक नहीं मिलता था। मैंने इसी सदन में यह मामला उठाया था। मंत्री जी, मैं आप से भी यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने आपका वक्तव्य देखा और उसको देखकर मुझे तकलीफ भी हुई। आपने यह कहा है कि गेहूं की जो फसल अति बारिश से और तेज हवाएं चलने से गिर गई है, वह उठ जाएगी। मैं खेत के किसान की एक तस्वीर आपके पास भिजवा रहा हूं। यदि मैं और आप दोनों मिलकर लगेंगे, तो भी यह फसल नहीं उठेगी। आपको संसद में ऐसे वक्तव्य देने से पहले किसानों की संवेदनाओं को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनसे उनको कितना कष्ट होता है। प्रो. राम गोपाल यादव जी यह बता रहे थे कि लगभग 98 प्रतिशत आलू सड़ कर खराब हो चुका है। इसके अलावा यह प्रकोप यहीं तक नहीं है, गेहूं की फसल लगभग गिर चुकी है, दहलन, तिलहन बरबाद हो चुका है और आलू की फसल के बारे में अभी प्रो. राम गोपाल यादव जी बता रहे थे। अभी नुकसान की रिपोर्ट आई नहीं है और मंत्री जी ने इस विषय में सोमवार तक का वक्त दिया है। सरसों सबसे नाजुक है और उस पर तो हवा क्या, जरा सा भी कुछ गिरे तो भी वह खराब हो जाती है। इन दिनों सरसों की फसल काफी मैच्योर सिचुएशन में होती है। हम गांव के लोग हैं, इसलिए हम जानते हैं और मार्च के महीने में उसे निकाल लेते हैं। अब की बार सरसों में कुछ निकलने वाला नहीं है। मटर पर ओले का प्रकोप होने से वह खत्म हो गई है। चना बरबाद हो गया है। सर, केवल इतना ही नहीं, इस बार...(**व्यवधान**)... मानसून की जो निष्क्रियता है, inactivity है, उसकी वजह से बुवाई भी देर से शुरू हुई है, लगभग 90 per cent बुवाई देर से शुरू हुई है, इसलिए मैं आप से यह कह रहा हूं। आपका पहला वक्तव्य ठीक है और उसकी वजह से गेहूं में दाना बनना शुरू हुआ था, जिसको मिल्क स्टेज बोलते हैं। उस पर जरा सा भी कोई प्रेशर पड़ेगा, तो वह चिपक जाएगा,

उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा और दोनों दाने पतले भी हो जाएंगे और कम भी हो जाएंगे। जो गेहूं के उत्पादक राज्य हैं, वे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और मध्य प्रदेश हैं। यदि यहां मेरे मध्य प्रदेश के साथी बैठे हों, तो मैं उनको बताना चाहूंगा कि इस समय मध्य प्रदेश में रिकार्ड उत्पादन हो रहा है।

सर, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कृषि मंत्री महोदय जानते हैं कि भारत के किसानों ने और कृषि वैज्ञानिकों ने आज भारत को इतना महान बनाया है कि हिन्दुस्तान का किसान इस समय दुनिया में नम्बर वन पर गेहूं भेजने वाला है, नम्बर दो पर चावल भेजने वाला है और नम्बर तीन पर शक्कर भेजने वाला है। लेकिन यह सरकारी मदद से कम और कृषि वैज्ञानिकों तथा किसानों की मेहनत से ज्यादा संभव हो पाया है। इसके साथ-साथ यह बीमारी यहीं तक नहीं है, बल्कि नागपुर के संतरे पर भी चोट आई है। जो नागपुर के संतरे की फसल है, वह बरबाद है। पुणे के अंदर जो अंगूर की फसल है, वह भी बरबाद है और आपके यहां जो केसर मैंगो होता है, जो देश में ही नहीं, अपितु पूरी दुनिया में जाता है, यह इस बार बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके साथ-साथ नींबू की फसल भी बरबाद है, इसलिए मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि आप सोमवार तक कह रहे हैं कि इसकी रपट आएगी, आप इसकी रपट भी मंगा लीजिए। अगर मैंने उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा नहीं की तो शायद मैं उसके साथ ज्यादती करूंगा। उत्तर प्रदेश सरकार देश की अकेली ऐसी सरकार है, जिसके मुख्य मंत्री ने किसानों को तत्काल राहत के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 50 फीसदी से अधिक फसल की क्षति होने पर लघु व सीमांत किसानों को असिंचित क्षेत्र में 4500 रुपए रुपए प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्र में 9,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई जाए, इसका आदेश दिया है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि एक किसान पुत्र होने के नाते, उन्होंने अपने फर्ज का निर्वाह किया है, हालांकि यह कम है।

चूंकि आपके घोषणापत्र में कृषि राहत प्राधिकरण जैसे शब्दों का बहुत इस्तेमाल होता है, कोई बुरी बात नहीं है। मेरा आप से निवेदन है कि इसके लिए एक कृषि राहत प्राधिकरण बनाया जाए। जो आपकी टीमें हैं, वे डिजास्टर मैनेजमेंट से भी इसकी मदद ले सकती हैं और इसके आकलन के लिए राज्यों में उन्हें भेज सकते हैं। लेकिन अभी मेरे पूर्व के कई साथियों ने आपसे जो निवेदन किया है और आने वाले 6 महीने की हमारी जो इकोनॉमिक्स है, यह उसका बेस है, आप जानते हैं। गेहूँ होगा, तो शादियाँ भी होंगी; गेहूँ होगा, तो एग्जाम के बाद नए एडमिशंस भी होंगे। इसलिए जितने भी रेवेन्यू कलेक्शन के काम हैं, उनको तत्काल रोक दिया जाए। फिलहाल मैं इस सरकार से इसे माफ करने की उम्मीद नहीं करता, चूँकि इस देश के बड़े पूँजीपतियों पर बैंकों और फाइनेंशियल इस्टीट्यूशंस के 5 लाख करोड़ रुपए बकाया हैं, लेकिन कारपोरेट की मस्ती में मस्त सरकार ने आज तक एक काम ऐसा नहीं किया कि इनसे पैसा वापस लेने की कोई प्रक्रिया शुरू हुई हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. राजीव) : त्यागी जी, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के.सी. त्यागी : माफ कर दिया। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप माफ नहीं करते हैं, तो इसे रोका जाए। जो धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है, वह तो उत्तर प्रदेश के कोटे की है। जो

[श्री के.सी. त्यागी]

सेंट्रल राहत कोष है, उससे जो पूरा नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए यहाँ से भी कुछ पैसा किसानों के लिए जाना चाहिए। मुझे याद आ रहा है, मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ, यह अब की नहीं, 1982 की बात है। चौधरी देवी लाल जी हरियाणा के मुख्य मंत्री थे, हम उनके साथ थे। सोनीपत जिले में गेहूँ की 100 परसेंट फसल बरबाद हो गई थी। उस मंदे जमाने में चौधरी देवी लाल जी ने 200 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से दिए थे और तभी से किसानों की परंपरा चली थी, वरना उससे पहले किसानों की फसल का नुकसान हो रहा है, कोई नोटिस नहीं लेता था। लिहाजा मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए मंत्री महोदय से उम्मीद करूँगा कि अपनी ग्रामीण पृष्ठभूमि की प्रखरता को पहचानते हुए, गाँधी की कर्मभूमि का ध्यान रखते हुए वे ऐसे प्रोविजंस कराने में कामयाब होंगे, ताकि आने वाले समय में, सरकारें तो आती जाती हैं, लेकिन राधा मोहन सिंह जी के जरिए कोई अच्छा काम हुआ था, हम लोग इसे याद करेंगे।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. RAJEEVE): Thank you. Shri D. Bandyopadhyay.

SHRI D. BANDYOPADHYAY (West Bengal): Thank you, Sir. During our college days, more than half-a-century ago, we were told that Indian agriculture was dependent on vagaries of the monsoon. If we take monsoon as rain, then it still depends on the vagaries of rain. With less than fifty per cent of the arable land still remaining unirrigated, late monsoon or scanty rainfall creates drought conditions adversely affecting agriculture. Similarly, heavy rainfall, particularly, if it is untimely, causes equally adverse effect on agriculture. In the winter, light rainfall is necessary before the flowering of wheat and also for potatoes. But, if it rains heavily, it becomes a curse. This shower, which if it had happened a little earlier, would have been highly welcomed by the farmers, but today it has become a curse for them. We do not have any firm figures. These are still being estimated. But the guess is that it is going to be severe unless very strong Sun comes out and does some drying up action. What is tragic is that we had a good harvest, but that good harvest is getting lost. It is like boat having reached the shore, sank. Sir, the States affected, as per information in the newspapers, are northern parts of Uttar Pradesh, Haryana, Madhya Pradesh, Rajasthan, Delhi, J&K, Uttarakhand, Himachal Pradesh, Punjab, Maharashtra and Gujarat. Special assistance should be given to all farmers who have lost their crop and it should be taken as a matter of course in future for all similar activities. The crops affected by the stem collapse, as per the report, are wheat, mustard, gram, potatoes, mango flowers, early mango in the northern region, grapes, cashew nut and oranges. Sir, this phenomenon

reiterates the necessity of universal crop insurance. Without any cumbersome procedure, those farmers, whose names are in the record of rights, should be given compensation, and a small insurance fee may be realised from them along with the land taxes so that no new bureaucracy is created which may create more hindrance than help.

Sir, I would like to conclude by saying that the Government should take necessary steps for all the affected States and arrange for economic rehabilitation of those farmers who have lost their crops. Thank you, Sir.

श्री राजपाल सिंह सैनी (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे अल्पकालिक चर्चा में, "बेमौसम आसमानी आफत से किसानों की तबाही" विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। इसके साथ ही मैं अपनी पार्टी की नेता, बहन कुमारी मायावती जी को भी धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझे किसानों के भारी नुकसान पर, उनकी बात को सदन में उठाने का अवसर दिया।

महोदय, पिछले तीन दिन से एनसीआर और उत्तर-पश्चिमी भारत में लगातार बारिश हो रही है। ओलों और तेज हवाओं ने किसानों को बेहाल करके रख दिया है, बरबाद करके रख दिया है।

महोदय, किसानों की गेहूं की फसल पक कर करीब-करीब तैयार होने के कगार पर थी, जिसको इस आसमानी आफत ने बिल्कुल नष्ट कर दिया है। आज गेहूं की तमाम फसल धरती पर बिछ गई है, जिससे किसानों को बहुत भारी नुक़सान हुआ है।

महोदय, खाली गेहूं की फसल ही नहीं, गेहूं के साथ-साथ सरसों की फसल, जो किसान के यहां एक बहुत नाजुक फसल समझी जाती है, वह भी बहुत भारी तादाद में इस नुकसान की चपेट में आ गई है। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं, हमारे यहां काफी बड़ी तादाद में आलू भी पैदा होता है। आज आलू की स्थिति ऐसी है, आलू के खेतों में खूब पानी भर गया है और वह सड़ने के कगार पर है। किसान को डर सता रहा है, क्योंकि वह आलू हरा भी हो सकता है और उसमें अंकुर निकलने का खतरा भी बना हुआ है।

महोदय, मेरा क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर है। मेरे ही जनपद से मेरे छोटे भाई सरकार में राज्य मंत्री हैं। माननीय कृषि मत्री जी भी किसान हैं। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे वे किसानों के दर्द को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आता हूं। आप जानते हैं कि यहां के किसानों की हालत तो पहले ही बहुत दयनीय स्थिति में पहुंच चुकी है।

पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल भी बहुत बड़ी तादाद में पैदा की जाती है। एक तो इस बार किसान को गन्ने का सही मूल्य मिल ही नहीं रहा है, दूसरा कम मूल्य मिलने के बाद भी उसको उसकी पेमेंट नहीं मिल रही है। पिछले साल का ही किसानों का अरबों रुपया मिल मालिकों पर बकाया है। किसान हर रोज़ इसके लिए धरना दे रहे हैं, परेशान हैं, सड़क पर है, तबाही के कगार पर हैं,

[श्री राजपाल सिंह सैनी]

लेकिन अभी तक उसका गन्ने का पेमेंट भी उसको नहीं मिल रहा है। महोदय, किसान को उम्मीद जगी थी कि गेहूं, आलू और सरसों की फसल से उसके नुकसान की कुछ भरपाई होगी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उसका यह मनसूबा भी चकनाचूर कर दिया है।

आज मैंने अखबार में पढ़ा, हालांकि मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि एग्रीकल्चर मिनिस्टर स्वयं एक किसान हैं। अखबार में मैंने पढ़ा, उसमें एग्रीकल्चर मिनिस्टर का एक बयान था कि किसान को 10% से 20% ही नुकसान हुआ है, अभी श्री के.सी. त्यागी जी भी कह रहे थे, कि किसान का जो गेहूं धरती पर लेट गया है, वह फिर से उठकर खड़ा हो जाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि ऐसा कभी भी सम्भव नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं एक किसान हूं, किसान का बेटा हूं।

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, उन्होंने जो कहा और मेरे पास जो कटिंग भेजी गयी है, वह बयान दूसरा है। आप भी बोल रहे हैं, तो मैंने कहाँ बोला है? मेरा बयान तो अभी यहाँ होना है।

श्री राजपाल सिंह सैनी(उत्तर प्रदेश)ः मैंने अखबार में पढ़ा है और उसमें से बोला है। हालाँकि मुझे उस पर विश्वास नहीं हुआ।

[**श्री उपसभापति** *पीठासीन हुए]*

श्री राधा मोहन सिंहः महोदय, हो सकता है कि किसी अखबार में आया हो, तो वह ज़रा मिल जाये। मैंने तो अभी कहीं बयान नहीं दिया है।

श्री राजपाल सिंह सैनीः मैं आपको अखबार दे दूँगा।

श्री राधा मोहन सिंहः वह कटिंग आप मुझे दे दीजिएगा।

श्री राजपाल सिंह सैनीः वह 'दैनिक जागरण' या 'अमर उजाला' में है। मैंने उसमें यह बयान पढ़ा है। हालाँकि मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि मैं किसान हूँ और कोई किसान इस बात को नहीं कह सकता कि गेहूँ की जो फसल धरती पर लेट जाय, वह खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं हो सकता। डा. संजीव कुमार बालियान जी बैठे हैं। ...(**व्यवधान**)... मैं जानता हूँ कि आपके कहने से किसान नहीं हो जाएँगे और न ही आपके सर्टिफिकेट की जरूरत है। मैं जानता हूँ कि कौन किसान हैं। ...(**व्यवधान**)... आपका बीच में बोलना जरूरी नहीं है। आप बैठ कर सुनिए। अगर आप किसान हैं, तो किसान का दर्द आपके दिल में होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)...

सर, मैं फिर एक बार माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूँ कि मुझे विश्वास नहीं हुआ कि यह आपका बयान होगा, लेकिन एक तरह से दुख हुआ। चलिए, मैं तो आपके सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूँ, मैं संतुष्ट हो जाऊँगा, लेकिन भारत के जिस किसान ने यह पढ़ा होगा कि हमारे कृषि मत्री का इस तरह का बयान है, तो उस किसान को कितना दुख हुआ होगा। चलिए, कोई बात नहीं, इसकी

भरपाई करने का पूरा मौका आपके पास है।

मान्यवर, इस आपदा में किसान के मनसूबे चकनाचूर हुए हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि जैसी स्थिति में आज किसान पहुँच गया है, वह आत्महत्या करने को मजबूर है। अभी लोगों ने बताया कि गेहूँ की फसल पर उसका काफी कुछ डिपेंड करता है। वह अपने बेटे-बेटी की शादी भी गरमी में करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए एडमिशन भी इसी गेहूँ को बेच कर कराता है, लेकिन अब वह सड़क पर है। उसका कोई पुरसाहाल नहीं है।

मान्यवर, सिर्फ गेहूँ का ही नुकसान नहीं हुआ है, जो अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे। पशुओं के चारे का भी नुकसान हुआ है। जो गेहूँ की फसल धरती पर लेट गयी, उसका भूसा नहीं बन पायेगा। तो वह भी किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, मेरा आपसे एक अनुरोध है। यह एक बहुत इम्पोर्टेंट इश्यू है, लेकिन आज महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जिस तरीके से चर्चा हुई और वोटिंग हुई, वह नेशनल न्यूज बन गयी।

श्री उपसभापतिः आप लोगों ने बनायी है।

श्री नरेश अग्रवालः सर, आज सारा मीडिया उसको दिखा रहा है। यह किसानों से जुड़ा मामला है। इसको मीडिया आज लेगा भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि इस पर कल सुबह डिस्कशन करा लें और जब कृषिं मत्री जी जवाब दें तो पूरे देश का किसान सुन पाए। इस वक्त कोई किसान इसे नहीं सुनेगा। इस चर्चा को कौन देख रहा है? कहाँ सब जगह टेलीविजन है? यह किसी अखबार में नहीं छपेगा। इसलिए, आप इसे कल करा लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री जी, मेरे ख्याल से इस पर आप भी तैयार होंगे। इसको कल कराने से पूरे देश का किसान इसे जान सकेगा। ...(**व्यवधान**)...

श्री किरनमय नन्दा (उत्तर प्रदेश): सर, इससे पूरे देश की सुरक्षा होगी। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः ताकि किसान जान सके कि हम लोगों ने क्या चर्चा की और मंत्री जी ने क्या जवाब दिया। ...(**व्यवधान**)...

श्री राजपाल सिंह सैनीः मान्यवर, ...(**व्यवधान**)... नहीं, मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। ...(**व्यवधान**)... मैं अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। मेरी बात दो मिनट में पूरी हो जायेगी।...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Let him speak. ...*(Interruptions)*...

श्री राजपाल सिंह सैनीः मैं अपनी बात बीच में अधूरी थोड़े ही छोड़ूँगा? ...(**व्यवधान**)... मैं कल क्यों बोलूँ? ...(**व्यवधान**)... मैं तो अभी बोल रहा हूँ। मान्यवर, मैं अपनी बात दो मिनट में पूरी कर रहा हूँ।

श्री उपसभापतिः सैनी जी, आप बोलिए।

श्री राजपाल सिंह सैनीः मान्यवर, आप एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, किसान हैं। किसान का दर्द आप बखूबी समझते हैं। किसान आज किस परिस्थिति में है, वह आपको बताने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपने जो सोमवार तक का टाइम दिया है, वह रिपोर्ट मँगा लें। मेरी माँग है कि किसान का जो नुकसान हुआ है, उसका पूरा आकलन आप करा लें। जो यह बता रहे हैं कि इतने हजार रुपये प्रति हेक्टेयर या इतने हजार रुपये प्रति एकड़ किसानों को देने का काम करें, तो उसका जितना नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कर दें, क्योंकि उसके पास आज कुछ नहीं है। वह आगे नहीं बढ़ सकता। वह अपना काम आगे नहीं कर सकता। मंत्री महोदय, उसका जितना नुकसान एक्चुअली हुआ है, उसके उतने नुकसान की भरपाई कर दें। किसान के उपर यह आपकी बहुत मेहरबानी होगी। अभी माननीय प्रधान मंत्री जी जो किसानों के बारे में कह रहे थे, किसान के लिए हमारे दिल में बहुत दर्द है, तो आप उनसे भी बात कीजिएगा और किसान का जो नुकसान हुआ है, आप उसकी पूरी भरपाई करने का काम करें। इसे किसी स्टेट गवर्नमेंट के भरोसे न छोड़ें, जो तिवारी जी कह रहे थे कि स्टेट गवर्नमेंट को आप 10 हजार करोड़ रुपये भेज दें। आप आँख बंद करके सीधे किसान के खाते में उसे भेज दें तो वह ज्यादा बेहतर होगा। मैं अपनी बात इस उम्मीद के साथ समाप्त करता हूँ कि मैंने जो कहा है, ...**(समय की घंटी)**... किसान की व्यथा आपके सामने कही है, उसको आप पूरा कराने का काम करेंगे। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राधा मोहन सिंहः सर, मैं एक clarification देना चाहता हूँ। ...**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः सर, इसको कल के लिए accept कर लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री राधा मोहन सिंहः सर, मेरी बात तो सुन ली जाए। अभी पहले भी माननीय तिवारी जी ने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 9 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर वहां सहायता देने का निर्देश दिया है। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूँ कि भारत सरकार, एनडीआरएफ का यही रूल है कि जो rain-fed area है, उसमें 4500 रुपए प्रति हेक्टेयर, जो एरिगेटेड एरिया है, उसमें 9000 प्रति हेक्टेयर ....**(व्यवधान)**...

श्री नरेश अग्रवालः मंत्री जी, आप इसे कल बताइए। ...**(व्यवधान)**....

श्री राधा मोहन सिंहः सर, मैं बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में ...**(व्यवधान)**... पूरे देश में चलता है।...**(व्यवधान)**...

श्री उपसभापतिः मंत्री जी, आप यह details reply के समय दे दीजिएगा, अभी नहीं देना है। Now, I will do like this. We started the Short Duration Discussion only after 5.45 p.m. Even if we sit up to 7.00 p.m., it will be less than 1 1/2 hours. So, another one hour is needed. So, we will sit up to seven. Then, we will take a view.

SHRI SUKHENDU SEKHAR ROY(West Bengal): Only 15 minutes are left.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I am only saying, at seven I will take the view of the House and then we will decide. ..*(Interruptions)*...

SHRI KIRANMAY NANDA: Sir, actually what the Agriculture Minister says here will become national news. ..*(Interruptions)*...

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति महोदय, आप अभी सदन का view ले लीजिए। ...(**व्यवधान**)...

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख़्तार अब्बास नक़वी)ः सर, मेरा आपसे अनुरोध है कि अभी काफी माननीय सदस्य बोलने के लिए बचे हुए हैं, इसलिए सात बजे तक जितना हो सके, उतना कर लीजिए और कल ज़ीरो ऑवर की जगह पर जो बचे हुए माननीय सदस्य रहेंगे, वे अपनी बात खत्म कर लेंगे। ...(**व्यवधान**)... नहीं तो सर, हमारा यह अनुरोध है कि चाहे दस बजे तक हो, इसको आज ही पूरा कर लें। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः ठीक है, कल ज़ीरो ऑवर में इसको ले लें। ...(**व्यवधान**)...

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः तो ठीक है ...(**व्यवधान**)... इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कल ज़ीरो ऑवर में बाकी जो चर्चा बची हुई है, उसको खत्म करके माननीय मंत्री जी का reply करा लेंगे। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Anyway, let us sit up to 7.00 p.m. Then, we will take a decision. ..*(Interruptions)*..

श्री मुख़्तार अब्बास नक़वीः सर, कल ज़ीरो ऑवर में जो remaining discussion है, वह होगा और मंत्री जी का reply होगा। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Please, we will sit up to 7.00 p.m. Tomorrow you have two Bills. You include this and two Bills.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: There are three Bills.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: We will take up these from 2.00 p.m. onwards. Next, Mr. K.N. Balagopal.

SHRI MUKHTAR ABBAS NAQVI: Okay.

SHRI K.N. BALAGOPAL (Kerala): Thank you, Sir. This is a very serious subject. It is not necessary to speak much also. The entire North India and Karnataka are affected by the rains. Around 303 lakh hectares of wheat cultivation is there. About 95.7 million was the last year's total crop. Now, the entire rabi crop is affected. Sir, the Minister is there. मैं देख रहा हूँ कि मत्री महोदय बीच में कुछ जवाब भी दे रहे हैं, लेकिन आप अभी देखिए ...(**व्यवधान**)...

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री रवि शंकर प्रसाद): और आपको हिन्दी में बोलना भी है। ...(**व्यवधान**)...

श्री के. एन. बालगोपालः चलिए, मैं हिन्दी में बोलता हूँ, I am trying. सर, यह climate change का मामला है। यह issue climate change का है। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Balagopal, address the Chair.

SHRI K.N. BALAGOPAL: Sir, this is an issue related to the climate change. The climate change is a serious issue. It is happening everywhere. Even in Kerala, last December, there were heavy rains. As per season, our crop is generally not affected. But this time because of change in the climate, it has been affected. So, we have to look into the new issue of climate change. The Government has to do something on this issue. What we have to do immediately is the Government should depute a team to inspect and investigate the cause. Both the State Government and the Central Government should be involved in this. Proper compensation should be given. Unfortunately what is happening in our State of Kerala is, when some heavy floods are there, the Central Government is deputing some team. But the Central teams come very late. Then, we have drought. But when the Central team comes, you have floods. So, timely intervention by the Centre is very necessary.

Sir, we have raised many different issues. We raised the issues facing our sugarcane farmers. Then, earlier, we had discussed the Meena Kumari Report with the hon. Minister. We raised fishermen's issues. The hon. Minister gave a hearing on all these issues. We have certain issues concerning the rubber sector. Of course, the rubber sector does not come under the Ministry of Agriculture. But let me say one thing, Sir, that Indian farmers are losing ₹ 13,000 crores. There also, this Government is not doing anything.

Finally, on the present issue, I suggest that there should be a special initiative taken to study the climate change aspect thoroughly and, accordingly, some special protection

must be provided to the agriculture which gets affected due to the climate change. ...*(Interruptions)*... Mr. Deputy Chairman, Sir, some bilateral is going on. Bilaterals are going on everywhere. I have been compelled to speak today. I was interested in speaking tomorrow. But bilaterals are going on like this. It is very difficult. Even the hon. Minister is having some bilaterals.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: What do I do?

SHRI K. N. BALAGOPAL: Others are also having bilaterals. This is not proper, Sir. So, this is one thing that I wanted to suggest regarding the climate change. Climate change is one issue. But not only in this area, but I can give you an example of what happens in agriculture also. There is a small island in Kerala where, because of climate change, water has risen by one foot. The entire land is fully submerged into salt water. Agriculture is not possible. So, when we look into the climate change aspects and the untimely rains seriously, there should be some separate research and study group and some kind of a policy should be evolved about the climate change. These natural calamities will keep on happening again and again. The Central teams should visit immediately and give compensation on time. That is what I wanted to say regarding these untimely rains and what I expect from the Central Government. Thank you.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you, Mr. Balagopal. Now, Dr. Ashok Ganguly.

DR. ASHOK S. GANGULY (NOMINATED): Mr. Chairman, Sir, this is a national calamity. It is not only destruction of crops caused by rains in north India, but it is also a national calamity. It is immediately affecting the farming community and, in the longer term, it would affect the whole nation. It is not a passing trait. The climate change is upon us. This is the effect of the climate change. And, the next time we have an uncertain monsoon, it would have a big impact on inflation and there will be a large number of farmer suicides.

Hon. Minister, it is not only a damage to the standing crops, but there is also damage to the FCI godowns, which are in the open, where the crops would have been damaged and also the crops stored by the farmers in their own farms. So, it is a much bigger damage than what we are talking about. The nation must know the extent of the damage. I think you have to prepare the country about what the extent of the damage is. Now, as everybody has talked about, there is need for providing relief to farmers and farm

[Dr. Ashok S. Ganguly]

labourers also, because the farm labourers will be out of jobs. May I request, on behalf of my colleagues in this House, is a response from the Minister on the magnitude of the loss, what plans he has for providing immediate relief to the farmers and farm labourers, to make the nation aware that prices, not only of foodgrains but also of vegetables, fruits and general inflation is likely to go up, and that the overall economic growth might be also seriously affected. Hon. Minister, I would further request you that let us also prepare for a possibly uncertain monsoon. Therefore, the food stocks that we have in buffer is going to be extremely critical, because climate uncertainty, climate change and global warming have begun its impact on our country. We see it as an immediate impact but the impact is going to be in the longer term. I must thank the Chairman for giving me this opportunity because this is a much larger issue than what we are looking at. The nation must know from the Hon. Minister as to what steps are being taken both in the short term and in the long term. Thank you very much Chairman.

MR. DEPUTY CHAIRMAN : Now, Shri Anil Desai.

SHRI ANIL DESAI (Maharashtra): Thank you, Sir. Mr. Deputy Chairman Sir, once again the unseasonal rains in various states of the country have devastated the hopes of the farmer community. In my state of Maharashtra, untimely rains and hailstorms have caused a heavy damage to ready-to-harvest crops in several districts like Yevatmal in Vidarbha, Nasik & Jalgaon in Northern Maharashtra, Ratnagiri and Sindhudurg in Konkan, almost all eight districts of Marathawada, and Satara, Sangli districts in western Maharashtra.

Among the Rabi crops that got damaged the most are Wheat, Jowar, Mustard, Gram and Onion; the fruit crops that bore the brunt are mango and cashew nuts in Konkan and grapes in northern Maharashtra, oranges in Vidarbha and harvesting of turmeric too has been badly affected.

A near normal monsoon last year had revived the hopes of a good rabi season and farmers were almost ready to reap the harvest but unfortunate and untimely showers ruined their hopes and once again buried them under the piles of heavy loans. This situation leaves them to look at the Government for immediate help and support; else they are left with no alternative but to end their lives which is being witnessed for quite some time. This nature's fury has made a big dent on the rural economy of our country.

7.00 P.M.

Though the state government has issued instructions to the district collectors to conduct the loss assessment programme, the data of losses is yet to be compiled by the State Government departments, but it is estimated that around 70% of the crops have suffered extensive damage due to the prevailing weather conditions. At this juncture, the Central Government should immediately dole out special financial package to the Government of Maharashtra and other affected States too. Crop insurance policy framework should be redesigned with widened scope so that it would help the farmers. The Government should bear the burden of crop insurance premium for, at least, next few years so that famers who are under the heavy financial crunch get a space to breathe.

Since the last quite few years, it has become a regular feature that unseasonal rains lash down the States of the country due to climate change and effects of global warming have become a cause to worry about degradation of environment. Therefore, the Government should work out a long term strategy to minimize or control the vagaries of nature by taking effective steps in all directions so that agro economy like India can overcome the hurdles like unseasonal or untimely rains and farmer community can reap rich harvest and live a sustainable life. Thank you.

SPECIAL MENTIONS

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the discussion is not concluded. We will continue it later. I am now taking up the Special Mentions. Shri Bhupender Yadav to lay it on the Table. He is not here. Shri Vijay Jawaharlal Darda. He is not present.

Shri Anand Bhaskar Rapolu.

Demand for declaring August 7 as National Handloom Weavers' Day

SHRI ANANDA BHASKAR RAPOLU (Telangana): India's heritage will not be complete without taking the handlooms, handicrafts and other semi-skilled artisans into consideration. *Swadeshi* products, hand-woven khadi and the symbol of Charkha occupied a grand place in the Freedom Struggle.

On August 7, 1905, in Kolkata, the then Calcutta, at its famous Town Hall, under the chairmanship of Maharaja Mahinder Chandra Nandy, resolved and observed to wear hand-